



Memorandum of Agreement (MoA)

**For supplying Topographic data to Central/State Government
Ministries/Organisations/Agencies without cost as per
Pricing policy under National Map Policy-2005**

between

**Survey of India,
Department of Science & Technology
Government of India**

and

.....

.....

Government of

Dated:..... 20...

Memorandum of Agreement (MoA) between the Survey of India, Department of Science & Technology, Government of India and.....Government of for supplying Topographic Data base (TDB) data to Central/State Government Ministries/Organizations/Agencies without cost as per Pricing policy under National Map Policy-2005

1. This MoA is made between the Survey of India, Department of Science & Technology, Government of India, hence forth called SoI and the, Department of, Government of, henceforth called Indenting Agency (IA) for supply of Topographic Data base (TDB) data to Central/State Government Ministries/Organizations/Agencies with only data handling charges as applicable from time to time as per Pricing policy under National Map Policy (NMP)-2005.
2. The IA agrees to receive TDB data as per the terms of this MOA. The IA declares its commitment to the objectives of the MOA.
3. The tenure of the MOA is for the period IA is bound by the license terms for the data supplied by SoI.
4. NMP mandates SoI to prepare, maintain and update NTDB for the country. Further National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP), 2012 mandates all Government agencies to facilitate the data access of types described in the NDSAP policy of data generated out of public funds. Such Non-sensitive sharable data sets are to be made available with the access to all users. Licensing guidelines issued under NMP-2005, Map Restriction & Data dissemination policies of MoD/MEA of Government of India. Pricing policy guidelines under NMP-2005 issued by SoI/DST governs the data accessibility, pricing, licensing and data management with entries in Map Transaction Registry (MTR) for each and every data transaction.
5. The IAs need to follow the NMP guidelines and license agreement terms for use of the data supplied as part of this MOA. The IAs will be responsible for strict compliance of all guidelines for handling, safety and security of data supplied under this MOA.
6. Any value addition or Updation of any kind on supplied data by the IA will be shared with SoI alongwith relevant records/documents (as applicable) on regular basis in a time bound manner for incorporation in NTDB subject to qualifying the requisite quality and validation checks by SoI. However the obligation for taking security clearance from the Ministry of Defence for updated/value added data, if applicable, rests with concerned IA. Concerned IA will only be responsible for any violation of any kind in this regard; SoI will not bear any responsibility of any kind.
7. SoI will take security clearance from the Ministry of Defence for TDB data of all kinds. However responsibilities or obligations, if any, associated with such security classification assigned by Ministry of Defence for the data will be completed by IA while handling such data.
8. The supplied data will be issued under appropriate license by the SOI and this data will be not be shared with any other agency for any purpose.

9. The Digital data will be used in any Web application (s) by the IA with following obligations:
- a. No web service based on SoI TDB data will be provided by the IA, for internal or external uses, Web services provided from SoI Geoportal only have to be used for applications requiring TDB data as service.
 - b. Web application (s) should share the services based on value added data by IA only.
 - c. Web application (s) should be hosted in safe and secure manner strictly as per Govt. of India guidelines for hosting such web applications.
 - d. No direct/indirect digital data dissemination functionality should be provided to share the SoI data with other agencies in such web application.
 - e. Permission to use this digital data will be applicable for the intended purpose only i.e. for web application (s) of the particular project for which data supply has been approved by the authorities.
10. In case TDB data supplied to an IA under this MoA with handling charges is found to be shared with any private/commercial/other organization, full cost of the digital data is required to be paid by the IA.
11. No changes in the above mentioned conditions of the MoA will be made to relax any agreed terms and conditions.

Signed on the day, 20.. at

**For and on behalf of the State/Central
Department/Organisation/Agency
Govt. of**

**For and on behalf of Survey of India,
Department of science & Technology,
Government of India**



सत्यमेव जयते



अनुबंध ज्ञापन (एम०ओ०ए०)

केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मंत्रालयों / केन्द्र या राज्य
विश्वविद्यालयों/स्वायत्त निकायों / अर्धसैनिक बलों / संगठनों /
एजेंसियों / को निशुल्क स्थलाकृतिक डाटा की आपूर्ति हेतू

राष्ट्रीय मानचित्रण नीति- 2005 के अंतर्गत, मूल्य निर्धारण नीति के
अनुसार

भारतीय सर्वेक्षण विभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
भारत सरकार

और

.....

.....

.....

..... सरकार के मध्य

दिनांक :20.....

राष्ट्रीय मानचित्र नीति - 2005 के अन्तर्गत, मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और सरकार केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों / संगठनों / एजेंसियों के बीच स्थलाकृतिक डाटा बेस (टीडीबी) की निशुल्क आपूर्ति के लिए अनुबंध ज़ापन (एमओए)

- 1) यह अनुबंध ज़ापन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहा जाए और विभाग सरकार अब से मांगकर्ता एजेंसी (आईए) कहा जाए, के बीच तैयार किया गया है। राष्ट्रीय मानचित्रण नीति (एनएमपी) - 2005 के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार समय-समय पर लागू डाटा के रख रखाव सहित केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/संगठनों एजेंसियोंको स्थलाकृतिक डाटा बेस (टीडीबी) डाटा की आपूर्ति के लिए यह अनुबंध ज़ापन किया गया है।
- 2) इस अनुबंध ज़ापन की शर्तों के अनुसार स्थलाकृतिक डाटा बेस (टीडीबी) डाटा प्राप्त करने के लिए आईए सहमत है। आईए, एमओए के उद्देश्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता की घोषणा करता है।
- 3) मांगकर्ता एजेंसियों (आईए) के लिए इस अनुबंध ज़ापन का कार्यकाल उस अवधि तक के लिए वैध होगा जोकि लाइसेंस शर्तों के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा डाटा आपूर्ति के लिए निर्धारित की गई है।
- 4) राष्ट्रीय मानचित्र नीति (एनएमपी) देश के लिए एनटीडीबी तैयार करने, रखरखाव और अद्यतन करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अधिदेश देता है। फिर नेशनल डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसपी) 2012 सभी सरकारी एजेंसियों को लोक निधि से संचालित डाटा एनडीएसपी पॉलिसी में निर्धारित डाटा पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे गैर संबन्धित शेरबल डाटा सेट सभी प्रयोगकर्ताओं को पहुँच के साथ उपलब्ध कराता है। एनएमपी-2005 के तहत जारी लाइसेंसिंग दिशानिर्देश, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (एमओडी)/ विदेश मंत्रालय (एमईए) की मैप रेस्ट्रिक्शन एंड डाटा डिस्सेमिनेशन नीतियां / भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) / डीएसटी द्वारा जारी राष्ट्रीय मानचित्रण नीति-2005 (एनएमपी) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण नीति दिशानिर्देश, प्रत्येक डाटा लेन देन के लिए मैप ट्रॉजकशन रजिस्ट्री (एमटीआर) में प्रविष्टियों के साथ डाटा पहुँच, मूल्य निर्धारण, लाइसेंस और डाटा प्रबंधन।
- 5) मांगकर्ता एजेंसियों (आईए) को इस अनुबंध ज़ापन (एमओए) के अंश के रूप में प्रदान किए गए डाटा आपूर्ति के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय मानचित्रण नीति (एनएमपी) के दिशानिर्देशों और लाइसेंस एग्रीमेंट शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता है। मांगकर्ता एजेंसियां (आईए) इस अनुबंध ज़ापन (एमओए) के तहत आपूर्ति किए गए डाटा के संचालन, सुरक्षा और बचाव के लिए सभी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 6) आईए द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ों पर किसी भी प्रकार का मूल्य परिवर्धन या अद्यतनीकरण एनटीडीबी में समावेशन के लिए नियमित आधार पर समय बद्धरूप में सुसंगत रिकार्ड/दस्तावेजों (जो लागू हैं) सहित भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के साथ साझा किया जाएगा ताकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता और विधिमान्यकरण जॉच प्राप्त हो सके। तथापि संबंधित मांगकर्ता एजेंसी (आईए) के साथ अद्यतन / मूल्य वर्धित डाटा यदि लागू है, के लिए रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा (एनओसी) मंजूरी लेने की बाध्यता है। केवल संबंधित मांगकर्ता एजेंसी (आईए) इस संबंध में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- 7) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) सभी प्रकार के स्थलाकृतिक डाटा बेस (टीडीबी) डाटा के लिए रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेगा। तथापि डाटा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सौंपी गई ऐसी सुरक्षा वर्गीकरण से जुड़ी जिम्मेदारियां या बाध्यताएं यदि कोई हैं, तो ऐसे डाटा को संभालने के लिए मांगकर्ता एजेंसी (आईए) द्वारा पूरी की जाएगी।
- 8) आपूर्ति किया गया डाटा भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) द्वारा उपयुक्त लाइसेंस के तहत जारी किया जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए यह डाटा किसी अन्य एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

- 9) डिजिटल डाटा का उपयोग इंडेंटिंग ऐजेन्सी द्वारा निम्नलिखित बाध्यताओं के साथ किसी भी वेब अनुप्रयोगों में किया जाएगा :-
- ए) आंतरिक और बहारी उपयोग के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक डाटा बेस (टी०डी०बी०) के आधार पर उपयोग के लिए प्रदान की जाएगी । भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्रदान की गई वेबसेवाएं जियो पोर्टल को केवल टोपोग्राफिकल डाटाबेस (टी०डी०बी०) की सेवाओं के लिए आवश्यक अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।
- बी) मांगकर्ता ऐजेन्सी द्वारा केवल वेब अनुप्रयोगों का मूल्यवृद्धित डेटा के आधार पर सेवाओं को साझा किया जाना चाहिए ।
- सी) वेब अनुप्रयोगों की मेजबानी के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती और सुरक्षित तरीके से होस्ट किया जाना चाहिए ।
- डी) ऐसे वेब अनुप्रयोगों में अन्य ऐजेसियों के साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डाटा को साझा करने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में अंकीय डाटा का प्रसार प्रदान कार्यात्मक सुविधा नहीं की जाएगी ।
- ई) डिजिटल डाटा के उपयोग करने की स्वीकृति केवल मांग के उद्देश्य पर लागू होगी । उदाहरणतः किसी विशेष परियोजना के वेब अनुप्रयोगों के लिए जिसके लिए कि डाटा आपूर्ति प्राधिकारी द्वारा डाटा अनुमोदित किया गया है।
- 10) यदि अनुबंध ज्ञापन के तहत आईए द्वारा स्थलाकृतिक डाटा बेस (टीडीबी) की आपूर्ति किसी निजी / वाणिज्यिक एवं अन्य संगठन के साथ साझा की जाती है तो डिजिटल डाटा की पूरी लागत आईए द्वारा भुगतान की जाएगी ।
- 11) समझौते के नियम और शर्तों का शिथिलिकरण करने के लिए करार अनुबंध की उपरोक्त शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ।

हस्ताक्षर का दिन..... 201... स्थान

सरकार की ओर सेराज्य /
केन्द्रीय विभाग / संगठन / ऐजेंसी की ओर से

भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी
विभाग, भारत सरकार की ओर से